Threats of dire consequences received by top Officials of Anti-Smuggling Organisation

*264. SHRI M. KALYANASUNDARAM: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether some top officials in the anti-smuggling organisation of the Revenue Departments have been receiving threats of "dire consequences" from anonymous persons;

(b) whether these threats have immobilised the anti-smuggling set-up in the country and the worth of smuggled goods seized has been showing a declining trend for the last few months; and

(c) if so, the facts thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI SATISH AGARWAL): (a) Reports received by the Government do not indicate that any top officials of the anti-smuggling organisation of the Department have been receiving threats of "dire consequences". However, recently, a few instances of threatening anonymous telephone call to some officials have been reported.

(b) and (c). No Sir. However, the anti-smuggling set up has been suitably strngthened and reinforced and the menace of smuggling has been effectively contained. As a result, the value of goods seized by the preventive agencies has shown a declining trend. As against goods worth Rs. 36.00 crores seized in 1976, the goods seized in 1977 (upto September) are worth only Rs. 20.00 crores. On the other hand, the inward remittances (non-trade) of foreign exchange have shown a sharp increase during the current year.

सट्टा समाप्त किया जाना

2303. **डा० रामजी सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सट्टा प्रथा गांधीवादी अर्थ-व्यवस्था के खिलाफ है जिसके प्रति जनता सरकार वचनबद्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सट्टा प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु सख्त कदम उठाने का है ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) वस्तुओं में वायदे के सौदे जो ऊपर से सट्टे जैसे दिखाई देते हैं—जैसी कई प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों का प्रभाव स्थिरता लाने वाला हो सकता है क्योंकि उनसे कीमतों में होने वाली अन्तरमौसमी घटबढ़ बराबर हो जाती है । तथापि कुछ परिस्थितियों में, वायदे के सौदों का परिणाम भी अवांछनीय हो सकता है । इस प्रकार की गतिविधियों पर सरकार लगातार निगरानी रखती है और स्थिति के अनुसार उन पर पाबन्दी लगाती है अथवा उनको अन्यथा विनियमित कर देती है ।

सरकारी उपक्रमों को हुई हानि

2304. **श्री राघवजी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के कुल कितने उपक्रम चल रहे हैं ;

(ख) वर्ष 1975–76 और 1976–77 में प्रत्येक उपक्रम में कुल कितनी हानि हुई और उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक उपक्रम को कितनी शुद्ध हानि हुई ; और

(ग) इस हानि वाले उपक्रमों में कुल कितनी पूंजी लगी है और उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ?